श्री भूपेन्द्र सिंह मान : इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल है कि जब एक्चुअल कास्ट एकडी जाती है तो फिर क्या सब्सिडी फार्मर तक जाती है या वह इंडस्ट्रीयलिस्ट्स तक रहती है ।

श्री बलराम जाखड़ : अगर फार्मर को ज्यादा देना पड़ता है जो उसका बोझ उस पर पड़ता है और अगर फार्मर को ज्यादा नहीं देना पड़ता है तो बोझ कम पड़ता है ।

श्री भूपेन्द्र सिंह मान : आप जो कास्ट कैलकुलेट करते हैं उसका लाभ किसको जाता है ? जब आप कास्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसके हिसाब से तो किसान पे करता है तो उसको सबसीडी कैसे पहुंचेगी ?

श्री बलराम जाखड़ : उसको कम भाव पर पहुंचेगी ।

SHRI SARADA MOHANTY: I want to know from the Government, in view of the economic crisis, whether it proposes to reduce or abolish the financial subsidy being given to fertiliser?

SHRI BALRAM JAKHAR: It is under consideration.

चीनी का मूल्य

*2. **श्री रजनी रंजन साहू :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में चीनी का कुल उत्पादन कितना हुआ ;

(ख) चीनी के उत्पादन और मूल्य निर्धारण के संबंध में सरकार के दिशा-निर्देश क्या हैं ;

(ग) महाराष्ट्र और बिहार में गन्ने के प्रति एकड़ उत्पादन में कितने क्विंटल का अंतर है ; और

(घ) क्या सरकार चीनी का मूल्य कम करने के लिए कोई कदम उठाने का विचार रखती है ?

खाद्य मंत्रालय के (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) :

विवरण

(क) पिछले 3 मौसमों के दौरान चीनी का उत्पादन निम्न प्रकार था :-

(लाख/टन)

चीनी वर्ष	चीनी उत्पादन
1987-88 . .	91.10
1988-89 . .	87.52
1889-90 . .	109.89

1990-91 के चालु मौसम के दौरान 15 जुन, 1991 तक चीनी का कुल उत्पादन 116.63 लाख टन हो गया था जबकि पिछले मौसम की इसी तारीख को यह उत्पादन 106.94 लाख टन था ।

(ख) वर्तमान नीति के अनुसार प्रत्येक चीनी फ़ैक्ट्री द्वारा उत्पादित चीनी का एक विनिर्दिष्ट प्रतिशत सरकार द्वारा निर्धारित समान खुदरा कीमतों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से निर्धारित करने के लए लेवी चीनी के रूप में ले लिया जाता है। चीनी की शेष मात्रा को बाजार में खुली बिक्री के लिए वि नयमित ढंग से रिलीज़ किया जाता है।

(ग) 1889-90 के दौरान महाराष्ट्र और बिहार में प्रति एकड़ गन्ने का उत्पादन निम्न प्रकार था :-

विवरण

राज्य	क्विंटल/प्रति एकड़
महाराष्ट्र . .	359.2
बिहार . .	217.6

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए लेवी चीनी की खुदरा कीमत 1 जनवरी, 1989 से 5 रुपये 25 पैसे चली आ रही है। जहां तक खुले बाजार में चीनी की कीमतों का संबंध है, प्रत्येक माह खुली बिक्री चीनी की पर्याप्त मात्रा रिलीज करके तथा अन्य आवश्यक नियामक उपायों द्वारा चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने के प्रयास किए जाएंगे।

श्री रजनी रंजन साहू: सभापति महोदय, पिछली सरकार ने फरवरी-मार्च, 1991 में चीनी की कीमतें 95 पैसे प्रति के.जी. बढ़ाकर 25 लाख रुपये प्रति माह की सबसीडी चीनी मिलों को देने का फैसला लिया था। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि (ए) कीमत तय करने का मकेनिज्म क्या है? (बी) यह है कि सप्लाई के जो आंकड़े उत्तर में दिये गये हैं, उनके अनुसार उत्पादन बढ़ रहा है तो उन रेशियो से डिमान्ड कितनी बढ़ी है और उसका संबंध कीमतों के साथ क्या है? (सी) प्रश्न यह है कि क्या सरकार चीनी की कीमत को कम करने पर विचार कर रही है?

SHRI TARUN GOGOI: As regards the price of sugar, we have not raised the price of the levy sugar. We control the levy sugar and that has been constant since January, 1986 and that has been fixed at Rs 5.25. And regarding production, it has gone up and prices are also high because in January 1991 it was Rs. 9 and till June it has gone up to Rs. 9.80 and from July, it has slightly gone down. It is just five paise less. There is a downward trend.

SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Sir, the hon. Minister has just said that since 1986 the prices are the same. I would like to draw his attention towards the cabinet decision of March 1991, wherein it has been decided, as appeared in the press report also, that the Union Cabinet has decided to raise the issue price of sugar by 95 paise from the fixed price at Rs. 5.25 which he has said I wanted to know whether he is aware of the decision or whether he is aware of the decision or whether he is prepared to lower down the prices because the production has increased. My second supplementary Sir, apart from this... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: You want to put two supplementaries together?

SHRI RAJNI RANJAN SAHU: I am asking clarification on the first supplementary.

MR. CHAIRMAN: First supplementary and then the second supplementary you put together.

SHRI RAJNI RANJAN SAHU: At the same time I am also asking second supplementary. If you permit let him reply to the first supplementary then I will ask the second supplementary.

MR. CHAIRMAN: You put both together.

SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Sir, from the figure he has given the per-acre production in Maharashtra which is 359.2 quintal and in Bihar the production is 217.4. I would like to know from the hon. Minister whether he has got any plans to increase the production in Bihar—any possible plan to increase production of sugar in Bihar.

SHRI TARUN GOGOI: There was a small mistake in what I stated earlier. The date is 1-1-1989, and not 1-1-1986.

In fact, the earlier Ministry had recommended to raise the price but they have given some reasons for it. I would also like to add that in the meantime, the sugarcane prices were raised and even then, we have not raised the price of sugar though price of sugar in the open market went up.

Regarding difference in production between the States of Maharashtra and Bihar I do agree there is a difference, but that is due to climatic conditions, due to soil condition, due to more utilisation of fertilizer in Maharashtra, more irrigated area in Maharashtra compared to that in Bihar, But I have certainly taken

note of the suggestions made by the hon. Member and I shall try my level best to take all necessary steps to see that production in Bihar also steps up.

श्री शंकर दयाल सिंह : सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से कुछ जानना चाहूं उसके पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि मूल प्रश्नकर्ता ने यह कहा है कि पिछली सरकार ने चीनी के दाम बढ़ा दिये। हर व्यक्ति जानता है कि हर इलेक्शन के पहले जो सरकार रहती है वह बहुत चीजों के दाम बढ़ाती है और किस लिए बढ़ाती है, यह भी लोगों को मालुम है। यह दूसरी बात है कि पिछली सरकार ने चीनी के जो दाम बढ़ाए रिजल्ट में उसकी मिठास उनको नहीं मिली बल्कि कड़वाहट मिली। इस बात को हर आदमी जानता है। मैं इसको अपने सामने रखते हुए सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जिस तरह से टेक्सटाइल में जितने सिक मिल्स थीं उन सिक मिल्स को टेक ओवर कर के प्रोडक्शन बढ़ाया गया और सिक मिल्स को नये ढंग से चलाया गया, कसावट की गई और उससे हर जगह कम दाम पर कपड़ा मुहैया हुआ, क्या सरकार देश में बन्द पड़ी हुई चीनी मिलों का अधिग्रहण करने का विचार रखती है जिससे उनको चलाया जा सके और चीनी का उत्पादन बढ़ाया जा सके और मूल्यों का भी नियन्त्रण हो ?

SHRI TARUN GOGOI: This does not arise out of the main question. But anyway, I have taken note of the suggestion given by the Hon. Member.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीय सभापति महोदय, सन, 1971 से 1989 तक इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार में यह निर्णय लिया गया था कि चीनी निर्माण के लिए प्राइवेट कम्पनियों को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। हमारे शंकर दयाल सिंह जी ने पिछली सरकार की बात की। जब उनके दल की सरकार थी तो उस समय प्राइवेटाइजेशन का एक आन्दोलन चलाया गया था और उसके प्रवक्ता सामने बैठे हुए विरोधी दल के नेता की बगल में राम जेठमलानी जी (व्यवधान)

श्री सभापति : आप सप्लीमेंटरी कीजिये।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीय सभापति जी, विदेशों में घूम कर के उन माननीय सदस्य ने वी.पी. सिंह जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले यह कहा था कि अगर वी.पी. सिंह की सरकार आएगी तो नेशनलाइजेशन की पालिसी छोड़ कर प्राइवेटाइजेशन की पालिसी अख्तियार की जाएगी। अमरीका में उन्होंने प्रेस कान्फ्रेंस करके राम जेठमलानी जी ने कहा था। इस सदन का रिकार्ड आप दिखवा लीजिये उस में यह चीज अंकित है। मैं जानना चाहूंगा कि जो राजीव गांधी और इन्दिरा गांधी की नीति थी कि प्राइवेट मिलों को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, चीनी निर्माण के लिए कितनी चीनी मिलों को प्राइवेट लाइसेंस दिये गये वी०पी० सिंह की सरकार में और कितने दाम चीनी के बढ़ाए गए चन्द्रशेखर सरकार के समय में। मंत्री महोदय इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर दें।

SHRI TARUN GOGOI: I do not have the figures at the moment. I shall reply to him later.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : सभापति जी, इसका डिटेल सदन के समक्ष माननीय मंत्री जी रखें, या आप उनको निदश दे दें। अभी तैयार होकर नहीं आये हैं। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने उठाया है। अगले अपने टर्न पर मंत्री महोदय सदन को अवगत करायें कि कम्पनियों का कितना प्राइवेटाइजेशन किया गया, चन्द्रशेखर की सरकार ने कितना चीनी का दाम बढ़ाया और वी.पी. सिंह की सरकार ने कितना प्राइवेटाइजेशन चीनी मिलों का किया। इनका स्पष्ट उत्तर सदन के सामने आना चाहिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि इस समय खुले बाजार में चीनी का मूल्य 10 रुपये प्रति किलो है और राशन की दुकान पर बिकने वाली चीनी 6

रुपये के भाव पर बिक रही है, इन दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन हकीकत यह है कि राशन पर मिलने वाली चीनी उपभोक्ता को उपलब्ध ही नहीं है। चीनी का कोटा रिलीज होता है, डिपो होल्डर उसे उठाता भी है लेकिन राशन कार्ड होल्डर तक पहुंचने से पहले कई तरह की अनियमितताएं करके उस कोटा को ब्लैक में बाजार में बेच दिया जाता है। इसलिए मैं खाद्य मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि हालांकि राशन की दुकान पर मिलने वाली चीनी बहुत पर्याप्त नहीं होती है, तो भी जितना कोटा, जितना तय होता है, अगर 6 रुपये किलो के भाव से राशन कार्ड होल्डर को मिल जाए तो थोड़ी राहत तो उस गरीब को मिल सकती है। तो खाद्य मंत्री जी उस सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से बिकने वाली चीनी राशन कार्ड होल्डर तक पहुंच जाए इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या कदम उठा रहे है।

इसके साथ ही मैं एक और जानकारी लेना चाहती हूं। जवाब के भाग "ख" में कहा गया है कि हर फैक्ट्री जो चीनी उत्पादन करती है उसमें कुछ खास फीसदी लेवी की चीनी उठाई जाती है। सभापति जी, यह लेवी पर उठायी गयी चीनी बिकती तो एक ही दर पर है लेकिन अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग दाम पर उठायी जाती है। इस पक्षपात का क्या कारण है। हरियाणा में जो लेवी की चीनी उठायी जाती है उसका दाम सबसे कम दिया जाता है जबकि महाराष्ट्र और बिहार में ज्यादा दिया जाता है। क्या इस सबको बराबर करने के लिए कोई प्रयास केन्द्रीय सरकार की तरफ से होगा? ये दो जानकारियां मैं आपके माध्यम से चाहूंगी।

SHRI TARUN GOGOI: The open market prices of sugar vary from State to State because even though the statutory minimum prices are fixed by the Central Government, there is also the State advised prices which vary from State to State.

SMT. SUSHMA SWARAJ: Price of sguar is fixed by the Central Government and not by the State Government.

SHRI TARUN GOGOI: There are two types of prices. One is the statutory minimum price fixed by the Central Government. The other is the State-advised price which depends on the State Governments. Suppose, in Haryana, the cane price is more than in Bihar, then, the open-market price of sugar will also be more.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: He may have to correct his answer later after talking to his officers.

श्रीमती सुषमा स्वराज : मेरे पहले सवाल का जवाब दिलवाइये। वह ज्यादा अहम सवाल है, राशन कार्ड होल्डर को आप कैसे चीनी दिलवायेंगे।

SHRI JAGESH DESAI: Sir, I would like to know from the hon. Minister as to what is the price given to levy sugar in Maharashtra, Bihar, UP and Haryana and what are the reasons for giving Maharashtra lesser price because it is efficient? Are you going to punish those States which are inefficient? Would the Government review the prices being given to different States and follow the same pattern throughout the country? Will the Government look into this?

SHRI TARUN GOGOI: I will look into it.

MR. CHAIRMAN: Shri Chaturanan Mishra. (*Interruptions*)

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, we have got eight assurances this morning. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: He asked the Minister 'Will you look into it?' He said 'Yes; I will look into it.'

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, how many times will he look into it? To everybody, he is replying 'I will look into it'.

SHRI V. NARAYANASAMY: Some Ministers are also saying that they will note the suggestion. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: I cannot look into it.

श्री प्रमोद महाजन : सभापति जी, प्रश्न के पूर्वार्ध में उन्होंने पूछा था कि महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश में लेवी प्राइस क्या है ? क्या इसमें कोई अंतर है, और अंतर के कारण क्या हैं ? यह तो वह बतायें, बाद में लुक इंटु करें कि क्या करना है ।

SHRI VIREN J. SHAH: Does he have the information with him or not?

SHRI KAMAL MORARKA: He will look into this also.

SHRI TARUN GOGOI: I have already said that there is no difference in the levy issue price.

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, he has not replied to the question put by Mr. Jagesh Desai. Why don't you direct him? You should direct him. (*Interruptions*).

SHRI S. B. CHAVAN: Mr. Chairman Sir, there is no denying the fact that so far as the other price is concerned, there is a differece between Bihar and some other States and Maharashtra. The hon. Minister is prepared to look into the matter. If necessary, he will have this corrected. (*Interruptions*). The first is a statement of fact that there is a difference between Maharashtra and some other States. The hon. Minister has said that he is prepared to look into the matter to find out whether there is any adequate justification. If there is any, of course, he cannot help it. If there is no justification, certainly, he will look into it, for rectifying it.

SHRI A. G. KULKARNI: I would like to know from the Leader of the House whether he would rectify the mistake?

SHRI S. B. CHAVAN: I think, when the hon. Minister said that he would look into the matter, it presupposes that if there is adequate justification, he cannot help it. But if he comes to the conclusion that some review is necessary, certainly, he will do it. (*Interruptions*).

SHRI VIREN J. SHAH: The hon. Minister has not answered Mr. Desai's question in regard to the prices in different States.

MR. CHAIRMAN: Shri Chaturanan Mishra. (*Interruptions*).

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति जी, मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि बिहार में जो प्रति एकड़ ईख का कम उत्पादन होता है, क्या इसका ही कारण है कि बिहार के किसानों को साल-साल भर, दो-दो साल तक ईख की कीमत नहीं मिलती है ।

मैं मंत्री महोदय से इसके बारे में आंकड़े सदन को प्रस्तुत करने के लिए कहूँगा कि बिहार में किसान जो ईख बेचते हैं, उसका दाम पिछले कितने दिनों से बकाया पड़ा हुआ है । उनको दाम ही नहीं मिल पाता है, यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है । इसलिए इस बिंदु पर मैं सफाई चाहूंगा । दूसरी बात जो मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जो चीनी की कीमत तय होती है उसमें छोजा का, मोलासेस का, बगास का, यह कीमत इन्क्लूड नहीं की जाती है और साईस में विकास के कारण छोआ अब चीनी से ज्यादा इंपार्टेंट हो गया है क्योंकि मोलाइसेस एक बाय-प्रोडक्ट बहुत सा मेडिसिंज वगैरह होता है और इसलिए उसका दाम ज्यादा बढ़ गया है । . . . (**व्यवधान**) और चीजें भी मिलती है । और चीजें जो मिलती है वह सभापति महोदय, आपके लिए एप्लीकेबल नहीं हैं, इसीलिए मैंने नहीं कहा और मंत्री महोदय जवान आदमी हैं, उनके लिए मैंने छोड़ दिया है । तो मेरा यह प्रश्न है कि जो

चीनी का मूल्य निर्धारित हो उसमें छोआ और बगास का, जो शूगर का बाय-प्रोडक्ट है और जिसका आज की दुनिया में बहुत ज्यादा महत्व हो गया है, उसको इन्क्लूड करके चीनी का दाम घटाया जा सकता है ? क्या सरकार इन दोनों बिंदुओं पर विचार करेगी और जवाब देगी ?

An HON. MEMBER: He will look into it.

SHRI TARUN GOGOI: The cost of production in Bihar is high, the yield is also lower. That is why, it is a fact, many of these factories have become sick and they have not been able to pay to the sugarcane growers. That is a fact and that is why we are going to monitor the whole thing to see how production can be speeded up. It is also mainly the responsibility of the State Goversment to see how production of sugarcane can be increased in Bihar.

SHRI CHATURANAN MISHRA: My question was quite clear. what are the arrears? Why don't you tell us the period and the arrears? Now your Government is depending upon the rule of the marke, which is to make immediate payment. So make payment immediately, ensure it.

SHRI TARUN GAGOI: There are large arrears of cane price in Bihar. It was 34.9 per cent of cane dues as on 30-5-1991. It is the State Government which has has to ensure price to the cane growers.

श्री रजनी रंजन साहू : सभापति महोदय, बिहार सरकार के वे एक पार्टनर हैं तो क्या वे एनश्योर करेंगे कि बकाया का भुगतान कब करेंगे, न कि केन्द्र सरकार से पूछेंगे कि कब पेमेंट करेंगे । आपके समर्थन की सरकार जो बिहार में चल रही है, उनसे पूछ कर बताइए कि कब पेमेंट कर पायेंगे ?

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महोदय, मेरे प्रश्न का दूसरा हिस्सा जो है.... (व्यवधान)

श्री सभापति : वह बगास वाला नहीं दिया है ।

श्री चतुरानन मिश्र : मोलाइसेस और बगास का, उसकी कीमत का उचित मूल्य चीनी का मूल्य निर्धारण में लिया जाए उसके बारे में मंत्री महोदय ने नहीं कहा वही तो मुख्य विषय है और तभी चीनी का दाम घट सकता है वरना नहीं घट सकता ?

MR. CHAIRMAN: He wants to know whether, while fixing the price, you will take note of the byproducts, molasses and bygasse also.

SHRI TARUN GOGOI: Byproduct, I believe that it is taken into account by the Government while fixing the levy price.

MR. CHAIRMAN: Question No. 3.

SHRI K. G. MAHESWARAPP: I want to ask one question. You had promised. This is connected with this industry.

MR. CHAIRMAN: No, I did not promise. This is my right. (*Interruptions*) I want to make it clear that it is the right of the Chairman to decide.

SHRI K. G. MAHESWARAPPA: No, Sir, I want to put the question.

MR. CHAIRMAN: No, I am not permitting. Yes, Question No. 3.

SHRI K. G. MAHESWARAPPA: This amounts to discrimination.

MR. CHAIRMAN: No. Question No. 3.

मानसून के आने में विलम्ब होने से फसलों को नुकसान

*3. **श्री शांति त्यागी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि मानसून के आने में विलम्ब होने से उत्तरी-पश्चिमी भारत में